Dr. Raman Kumar Thakur **Assistant professor (Guest)Department of Economics D.B.College, Jaynagar, Madhubani,L.N.M.U.Darbhanga.** **Class:-B.A.part-1(Hons.)**
Date:-28.08.2020.

Lecture n.-33.

Topic:- मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं क्षेत्र :- मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सह-अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है ।

मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार को आर्थिक क्रिया के क्षेत्र में सकारात्मक भाग अदा करना पड़ता है। कुछ उद्योग तो ऐसे हो सकते हैं जिनमें पूर्णतया सरकारी स्वामित्व हो और कुछ ऐसे उद्योग हो सकते हैं जिनमें पूर्णतया सरकारी स्वामित्व हो ,और कुछ ऐसे उद्योग हो सकते हैं जिनमें राज्य और निजी उद्यम का साझा स्वामित्व एवं प्रबंध हो।

इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में देश की समग्र आर्थिक प्रणाली तीन भागों में बट जाती है जो इस प्रकार से देखा जा सकता है:-

1) ऐसे क्षेत्र में उत्पादन एवं वितरण का पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण राज्य के हाथ में होता है और निजी क्षेत्र को पूर्णतया नि:सारित कर दिया जाता है ।

2). ऐसे क्षेत्र जिनमें निजी उद्यम उत्पादन एवं वितरण में साझे रूप में सहयोग करते हैं।

3) ऐसे क्षेत्र जिनमें निजी उद्यम पूर्णतया क्रियाशील होता है और इस पर राज्य का सामान्य नियंत्रण एवं विनियमन होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक उद्यमों का सह-अस्तित्व होता है। हेनसन के शब्दों में दैध् अर्थव्यवस्था (Dual Economy) का प्रयोग किया।

भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का ढांचा :- मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे पहला महत्वपूर्ण लक्षण निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह -अस्तित्व है। संकुचित रूप में पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्थाऐ दोनों ही मिश्रित अर्थव्यवस्था में समझी जा सकती है क्योंकि प्रत्येक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र तो होगा ही और इसी प्रकार की समाजवादी अर्थव्यवस्था में छोटा सा निजी क्षेत्र भी होगा परंतु पूंजीवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था में एक छोटे से सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के अस्तित्व मात्र से ही अर्थव्यवस्थाऐ मिश्रित अर्थव्यवस्थाए नहीं बन जाती। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार विधानसभा के माध्यम से यह घोषणा करेगी यह इन दोनों क्षेत्रों निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सह अस्तित्व के लिए वचनबद्ध है। सरकार को इन

दोनों क्षेत्रों के कार्य क्षेत्र का भी निर्धारण करना होगा। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण समझा जाता है ।भारतीय संविधान के निदेशक सिद्धांतों के अधीन आर्थिक क्षेत्र में राज्य को अपनी नीति का इस प्रकार निर्देशन करना होगा कि इससे समाज के भौतिक साधनों के स्वामित्व बेहतर वितरण एवं नियंत्रण प्राप्त हो सके और इससे कुछ व्यक्तियों के हाथों में संपत्ति का संकेंद्रण और श्रम का शोषण रोका जा सके। भारत में, सरकार ने निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगो की प्रोन्नति के लिए क्षेत्र निर्धारण कर दिया है यह वर्गीकरण 1956 की औद्योगिक नीति में स्पष्ट किया गया। प्रथम, वर्ग में ऐसे उद्योग शामिल किए गए हैं जिनके विकास की पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाली गई। दूसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल किए गए जिनमें राज्य का स्वामित्व अधिकार बढ़ता जाएगा परंतु निजी क्षेत्र को सरकार के प्रयास में सहयोग देने की इजाजत होगी इन दोनों क्षेत्रों में राज्य अर्थव्यवस्था के मूल महत्व के उद्योगों का विकास करने के लिए जानबूझकर सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) का विस्तार करना चाहता है । इस प्रकार प्रतिरक्षा और भारी उद्योगों का विकास करके देश को विदेशी निर्भरता से मुक्त करना होगा ।और अध:संरचना सुविधाओं अर्थात पानी ,उर्जा, और परिवहन का विस्तार करके कृषि तथा उद्योग में विनियोग के

लिए अनुकूल परिस्थितियां करनी होगी। 1969 में मुख्य वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण द्वारा एक और बड़ा कदम उठाया गया ताकि उत्पादन के सामाजिक दृष्टि से वांछनीय क्षेत्रों में विनियोग निर्देशित हो सके। दूसरे एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अनिवार्यतः आयोजित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ केवल एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था से नहीं जिसमें सरकार आर्थिक मामलों में राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति द्वारा हस्तक्षेप करती है बल्कि यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार की एक स्पष्ट एवं निश्चित योजना होती है। सरकार के लिए योजना बनानी आवश्यक है । क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य संचालन निश्चित प्राथमिकताओं के आधार पर करना होगा ताकि निश्चित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। परंतु सरकार निजी क्षेत्र को अपने आप अव्यवस्थित ढंग से विकसित होने के लिए छोड़ नहीं सकती और इसलिए इसे एक योजना तैयार करनी होगी जिसमें निजी क्षेत्र का एक सुनिश्चित स्थान हो। तीसरे मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद के मुख्य लक्षणों का बहुत स्पष्ट एवं चतुर रूप में समायोजन किया जाता है उदाहरण के लिए निजी क्षेत्र के उद्योग निजी हित एवं लाभ- प्रेरणा(Profit Motive)पर

आधारित होते हैं । व्यक्तिक पहल की पूर्ण गुंजाइश रखी जाती है। और निजी संपत्ति का आदर किया जाता है।

इस प्रकार भारत में सरकार समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए वचनबद्ध है जिसमें संपत्ति की सुव्यकत असमानताऐ न्यूनतम कर दी जाएगी । परंतु राज्य नहीं चाहेगा कि वह निजी उद्यम प्रणाली को पूर्णतया समाप्त कर दें जो बहुत से दोषों एवं कठिनाइयों के बावजूद उत्पादन एवं वितरण के क्षेत्र में अच्छा कार्य करती चली आई है ।अत: हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था लोकतंत्र और समाजवाद में हमारे विश्वास का परिणाम है। इसके फलस्वरूप इसमें राजकीय क्षेत्र का विस्तार हुआ है।